सम्पूर्ण आजादी का दस्तावेज

डाईवर्सिटी

इयर बुक : 2015-16

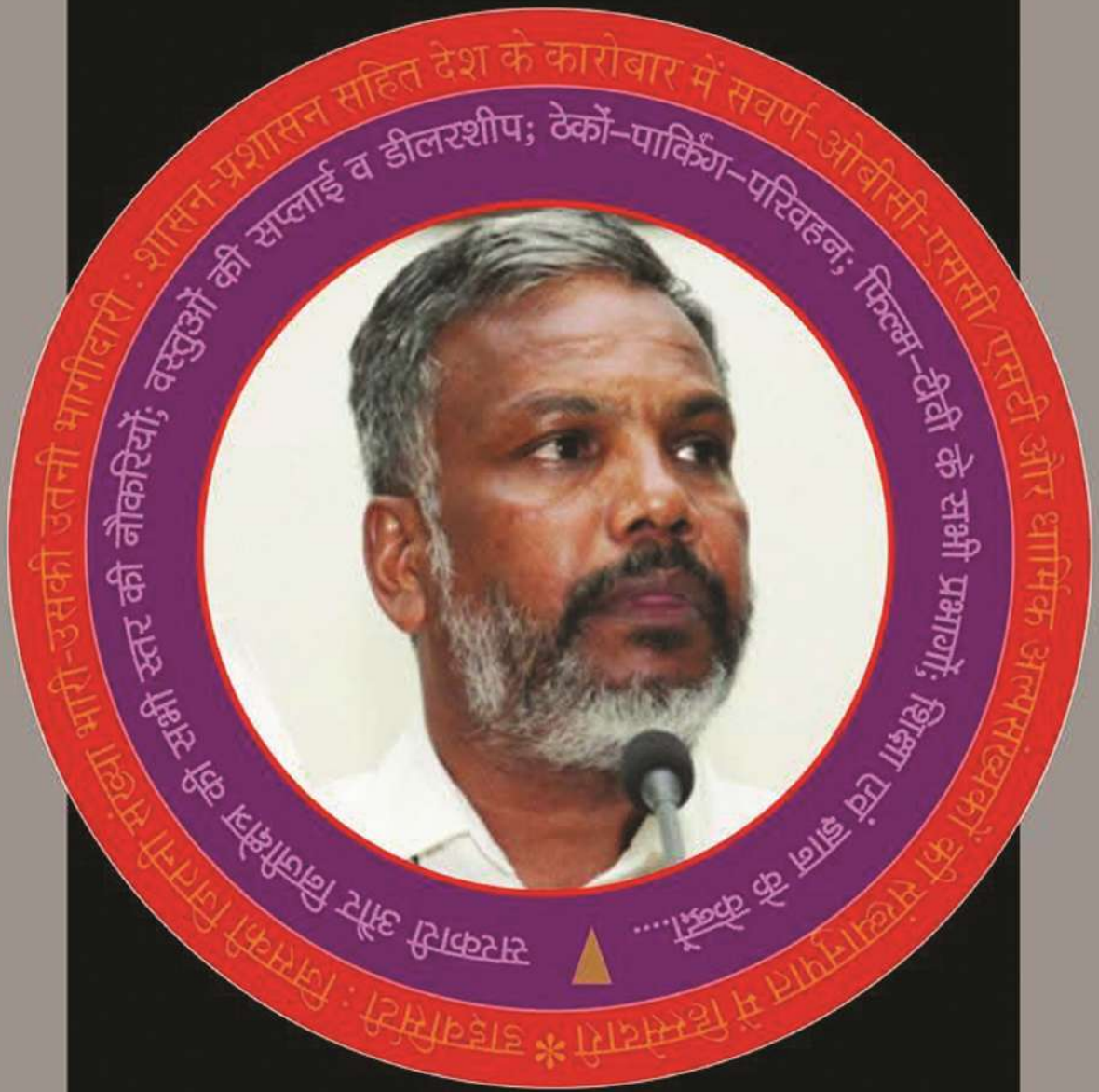

संपादक : एच.एल. दुसाध

सह-संपादक : अनिल कु. धवन-डॉ. कौलेश्वर

डाइवर्सिटी इयर-बुक

2015-16

सम्पादक

एच. एल. दुसाध

सह-सम्पादक

डॉ. अनिल कुमार धवन - डॉ. कौलेश्वर

दुसाध प्रकाशन

लखनऊ

प्रथम संस्करण : 2015

ISBN : 978-81-87618-62-1

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन के लिए
द्वारा
प्रकाशक : **दुसाध प्रकाशन**
डाइवर्सिटी हाउस, 2/1467,
आदिल नगर, कल्याणपुर, लखनऊ-226022
E-mail : hl.dusadh@gmail.com
मो. : 9654816191

प्रशासनिक कार्यालय
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6, नई दिल्ली-110047,

© **संपादक**

मूल्य : 2500.00 रुपये

रचना	:	**डाइवर्सिटी इयर-बुक : 2015-16**
संपादक	:	एच.एल. दुसाध
आवरण	:	राकेश यादव
शब्दांकन	:	कम्प्यूटेक सिस्टम, शाहदरा, दिल्ली-32
मुद्रक	:	क्विक ऑफसेट, दिल्ली-94

डाइवर्सिटी इयर बुक

2015-16 का संपादकीय परिवार

संरक्षक	:	**डॉ. संजय पासवान**
प्रेरणा मण्डल	:	**दिग्विजय सिंह, चन्द्रभान प्रसाद, सुधीन्द्र कुलकर्णी, डॉ. जगदीश प्रसाद, छेदी पासवान, डॉ. एस. एन. संखवार, डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल, सुरेश केदारे, डॉ. संजय वठोरे**
मुख्य परामर्शदाता	:	**बुद्ध शरण हंस, दिलीप मंडल**
परामर्श मण्डल	:	**डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, बृजपाल भारती, अभिजीत कुमार, सुदेश तनवर, डॉ. पी. एल. संखवार, आशिक भागलपुरी, डॉ. महेन्द्र प्रताप राणा**
संपादक	:	**एच.एल. दुसाध**
सह-संपादक	:	**डॉ. अनिल कुमार धवन - डॉ. कौलेश्वर**
संपादक मण्डल	:	**शीलबोधि, डॉ. चन्द्रशेखर राम, ललन कुमार, अनिल कुमार आर्य, राम किशोर यादव, डॉ. अमरनाथ, डॉ. कविश कुमार**

संपादकीय संपर्क : **एच.एल. दुसाध**
एफ-196, आया नगर एक्स, फेज-6
नई दिल्ली-110047
मो. 9654816191

21वीं सदी के दलित युवाओं के रोल मॉडल

डॉ. सुकेश राजन

को

सम्पादकीय

2006 से शुरू हुई डाइवर्सिटी इयर बुक का यह दसवां अंक है, जिसे विगत चार वर्षों की भांति एक बार फिर नियत तिथि पर न ला पाने की विफलता के लिए हम खेद प्रकट करते हैं। ऐसा होने का खास कारण यह है कि जिस 'डाइवर्सिटी डे' के अवसर पर इसका प्रकाशन होता है, उसका आयोजन 2010 के बाद लगातार पांचवीं बार निर्दिष्ट तिथि (27 अगस्त) पर करने में फिर विफल हो गए। हालांकि बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए इस बार 27 अगस्त को पटना में डाइवर्सिटी डे आयोजित करने की पूरी तैयारी कर ली गयी थी, पर उक्त तिथि तक वहां चुनाव संहिता लागू होने की आशंका से इसे 13 सितम्बर को जयपुर में करने का निर्णय लेना पड़ा। बहरहाल यह नया अंक पिछली वार्षिकी के असर से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

इयर बुक के पाठक भूले नहीं होंगे कि इसका पिछला अंक चुनावी विशेषांक था। इससे पहले ऐसा ही विशेषांक 2009 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें पंद्रहवीं लोकसभा चुनाव को 350 पृष्ठों में कवर किया गया था जबकि 2014 में 16 वीं लोकसभा के लिए लगभग 500 पृष्ठ खर्च करने पड़े थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस धूम-धड़ाके से मोदी सरकार सत्ता में आई और इसे लेकर जिस बड़े पैमाने पर न्यूज बना उससे हमारे सामने 2009 के मुकाबले और विस्तार से कवर के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहा।

मोदी सरकार के एक साल

वैसे केंद्र या राज्यों की सत्ता पर काबिज होने वाली हर सरकार के पहले वर्ष के कार्यकाल के प्रति लोगों में एक खास कौतुहल रहता है। ऐसा इसलिए कि पहले वर्ष के कामकाज के आकलन के आधार ही बाकि कार्यकाल का अनुमान लग जाता है। इस मामले में मोदी सरकार सबसे विरल रही। अच्छे दिन लाने का वादा कर इस सरकार ने लोगों की प्रत्याशा इस कदर तुंग पर पहुंचा दी थी कि इसके एक साल पूरा होने पर तमाम चैनल, अखबार और राजनीतिक विश्लेषक ही इसके कार्यों के आकलन में टूट पड़े। ऐसे में हमारे लिए भी इसे नजरंदाज करना कठिन था।

लिहाजा हमने इसके लिए शताधिक पृष्ठों में अखबारों और राजनीतिक विश्लेषकों की राय तो डाला ही, उससे भी आगे बढ़कर इयर बुक के स्थाई अध्याय, साक्षात्कार के दस में से पांच प्रश्न मोदी सरकार के एक साल पर केन्द्रित कर डाला। इस क्रम में पाठकों को मोदी सरकार के पहले साल के काम-काज पर सर्वाधिक सूचना से रूबरू होने का अवसर हम इस नई वार्षिकी के जरिये सुलभ करा रहे हैं। इस मुद्दे पर इस वार्षिकी में जो विपुल सामग्री संग्रहित हुई है उसके निष्कर्षों को यदि कुछ वाक्यों रखने का प्रयास किया जाय तो यही कहा जायेगा कि अच्छे दिन लाने का मोदी सरकार का वादा चुनावी जुमला बनकर रह गया है, जैसे कि भाजपाध्यक्ष अमित शाह ने विदेशों में पड़े काले धन से हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जमा कराने तथा युवाओं को 5 करोड़ नौकरियां दिलाने के वादे को चुनावी जुमला करार देकर हकीकत से रूबरू करा दिया। बहरहाल मोदी सरकार के पहले वर्ष में आम लोगों के मुकाबले दलितों को कुछ ज्यादे ही निराशा हुई।

भाजपा का दलित प्रेम छलावा

काबिले गौर है कि आंबेडकर प्रेम में औरों से आगे दिखने की होड़ में जहाँ भाजपा के मातृ-संगठन आरएसएस की ओर से बाबा साहेब डॉ.आंबेडकर को डॉ. हेडगेवार के समान बताते हुए भारतीय पुनरुत्थान के पांचवें चरण का अगुआ बताया गया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलान कर दिया कि यदि आंबेडकर नहीं होते तो मैं भी यहाँ नहीं होता। आंबेडकर के प्रति श्रद्धा का ऐसा उच्च उद्घोष सुनने के बाद लगा कि मोदी सरकार की ओर से दलित हित में कुछ चौकाने वाले कदम उठाये जा सकते हैं। ऐसा लगने के पीछे आंबेडकर प्रेम के साथ एक अन्यतम कारण यह भी था कि जिस तरह मोदी ने सत्ता दखल में सहायक बने बाघा-बाघा दलित सांसदों की अपने मंत्रीमंडल में उपेक्षा की, उसकी भरपाई के लिए वे दलित हित में कुछ खास कदम उठा सकते हैं। पर अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती मानने वाले आंबेडकर के लोगों के लिए कुछ खास करना मोदी सरकार ने जरुरी नहीं समझा। यदि जरुरी समझती तो और कुछ नहीं, पर अंततः प्रमोशन में आरक्षण का मामला हल कर ही देती। कारण, इससे जुड़ा बिल उस राज्यसभा में पारित हो ही चुका था, जहां भाजपा बेबस है। ऐसे में खुद राज्य सभा में प्रमोशन में आरक्षण बिल का बढ़-चढ़कर समर्थन करने वाली भाजपा चाहती तो लोकसभा में इसे आसानी से पास करा देती, जहाँ इसकी विपुल संख्या गरिष्ठता है। किन्तु वैसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा मोदी राज में देश वर्षों पहले प्रोन्नति में आरक्षण पाए दलित कर्मचारियों के पदावनत होने का दृश्य देखने के लिए विवश है।

बहरहाल अपने पहले साल के कार्यकाल में दलित उत्पीड़न में हुई बेतहाशा वृद्धि का खामोशी से साक्षात् करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अन्ततः दूसरी बार लाल किले

से राष्ट्र को संबोधित करते हुए दलित हित में मुंह खोला। उन्होंने 15 अगस्त, 2015 को लाल किले से अपील किया-' देश में बैंकों की सवा लाख शाखाएं हैं। मैं अपील करता हूँ कि इनमें से हर शाखा कम से कम एक दलित या आदिवासी उद्यमी को नया उद्योग लगाने के लिए कर्ज दे।' लेकिन बैकों से दलित उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपील करने वाले प्रधानमंत्री जी भूल गए कि दलित चाहें तो खुद से जैसे तैसे छोटा-मोटा उद्योग खड़ा कर लें। उनके सामने प्रधान समस्या तो उत्पादित वस्तुओं के सप्लाई की है, जहां से वे जातिगत कारणों से बहिष्कृत हैं। ऐसे में अगर मोदी दलित उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रति सचमुच गंभीर हैं तो सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, पार्किंग, परिवहन इत्यादि से उनका बहिष्कार दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए उन्हें राजसत्ता का इस्तेमाल कर इन आर्थिक गतिविधियों में दलितों का शेयर सुनिश्चित कराना होगा, जैसा कि सरकारी नौकरियों और राजनीति की संस्थाओं इत्यादि में उनके लिए किया गया है। किन्तु मोदी सरकार का पिछला एक साल बताता है कि भाजपा और उसके मुखिया, आंबेडकर प्रेम का जितना भी उच्च उद्घोष क्यों न कर लें, उनसे आंबेडकर के लोगों की बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती। बहरहाल मोदी-राज के शुरुआती आधे वर्ष में लोगों के जीवन में अच्छे दिन लाने लायक ठोस काम की जगह गीता को राष्ट्रीय ग्रन्थ और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ राम मंदिर निर्माण, घर वापसी, लव जिहाद जैसे भावनात्मक व सांप्रदायिक मुद्दों के बोलबाले के बावजूद भाजपा का विजय रथ धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा, जिसे स्तब्ध करने का हैरतंगेज काम कर डाला एनजीओ गैंग के सरगना ने।

फिर केजरीवाल

8 दिसंबर, 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के जरिये भारतीय राजनीति में अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराने तथा 28 दिसंबर, 2013 को दिल्ली में सरकार बनाने वाले केजरीवाल ने जब 14 फरवरी, 2014 को जनलोकपाल बिल पास कराने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति न मिलने पर सीएम पद से इस्तीफा दे डाला, बहुतों ने आम आदमी पार्टी को फिनिश मान लिया। विशेषकर मोदी की सुनामी में दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें गंवाने के बाद 'आप' को प्रायः सभी ने खत्म ही मान लिया। किन्तु यह बीडीएम से जुड़े लोग थे जो ऐसी खुशफहमी का शिकार न होकर 'आप' को भारतीय राजनीति का सबसे डेंजरस एलीमेंट्स बताते हुए राष्ट्र को निरंतर इससे सतर्क करते रहे। इयर बुक के पाठक भूले नहीं होंगे कि पिछले वर्ष 'आप' को भारतीय राजनीति का लाइलाज वायरस बताते हुए हमने इयर बुक में आप की राजनीति से जुड़े 100 पेज डाले थे। जिस आप से हम लगातार आगाह करते रहे उसने 10 फरवरी, 2015 को दिल्ली में इतनी धमाकेदार विजय हासिल की जिस की मिसाल भारतीय राजनीति में दुर्लभ है। दिल्ली में अभूतपूर्व विजय हासिल कर आप ने भारतीय राजनीति में अपनी स्थाई उपस्थिति दर्ज करा दी है।

इसी पार्टी के दुबारा सत्ता में आने के बाद जब योगेन्द्र यादव, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण जैसों को पार्टी से निकाल दिया गया, बहुतों को लगा इस बिखराव से पार्टी खत्म हो जाएगी तथा वैकल्पिक राजनीति के उभार की सम्भावना की भ्रूण-हत्या हो जाएगी। मेरा मानना है कि आप के बिखराव के बाद फिर राष्ट्र इस पार्टी के खतरे को कमतर आंकने की भूल कर रहा है। इससे राष्ट्र को आगाह करने के लिए ही हमने जहां गत 15 मार्च को बीडीएम के स्थापना दिवस के अवसर पर 256 पृष्ठों में 'जन लोकपाल बनाम डाइवर्सिटी : भारतीय लोकतंत्र पर एनजीओ गैंग की काली छाया' का परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित किया, वहीं पिछली बार के सौ की जगह इस बार इयर बुक में लगभग सवा सौ पन्ने आप के लिए आरक्षित किये हैं। इयर बुक के इस अंक के द्वारा गत वर्ष की भांति एक बार फिर बहुजनों को चेताते हुए बताना चाहता हूँ—'आरक्षण को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार घोषित करने के कारण आप सवर्णों की सबसे फेवरिट पार्टी बन चुकी है। इस कारण ही सवर्णों का आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़ा बेहतरीन टैलेंट आप के साथ है। इस कारण ही यूथ फॉर इक्वेलिटी की मानसिकता से पुष्ट सवर्णों के तमाम युवाओं की पहली पसंद आप है। इस कारण ही सवर्णवादी मीडिया का 1-9 तक पसंदीदा दल आप है। यदि आप वालों से सबक लेते हुए बहुजनवादी दल शक्ति के तमाम स्रोतों में बहुजनों को संख्यानुपात में हिस्सेदारी दिलाने व इस पर 80-85 प्रतिशत कब्जा जमाये सवर्णों को 15 प्रतिशत पर लाने की खुली घोषणा करें तो वे आप की सफलता का रिकार्ड पुरे देश में दोहरा सकते हैं। जब तक वे ऐसा नहीं करते, देश को एनजीओ वालों के हाथ में देखने के लिए अभिशप्त रहेंगे।'

भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे सवर्णवादी दल के रूप में उभर चुके आप को रोकने में बहुजनवादी दलों का मुस्तैद होना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि भविष्य में जो इसका विस्तार होने जा रहा है वह चर्चित बहुजन चिन्तक दिलीप मंडल के शब्दों में—' इस बात में संदेह का कोई कारण नहीं कि अगर आम आदमी पार्टी का विस्तार होता है, तो यह सेकुलर, बहुजनवादी और वामपंथी दलों की कीमत पर ही होगा। इसलिए तीसरी धारा के दलों और वामपंथी पार्टियों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत पर खुश होने का नहीं, सावधान हो जाने का मौका है।' बहरहाल मई, 2014 से फरवरी, 2015 के मध्य जब भाजपा और आम आदमी पार्टी जैसे सवर्णवादी दलों के उभार से वंचित दलित-बहुजन त्रस्त थे उसी बीच हवा के सुखद झोंके की भांति जीतनराम मांझी का उदय हुआ।

बहुजन राजनीति की नई उम्मीद : जीतनराम मांझी

नवम्बर, 2014 के पहले सप्ताह तक राजनीति का बड़े से बड़ा पंडित भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि 6 अक्तूबर, 1944 को बिहार के गया जिले के खिजरसराय

प्रखंड के महकार गाँव में दलितों की सर्वाधिक पिछड़ी, मुशहर जाति में जन्मे जीतनराम मांझी बहुजन राजनीति की एक नयी उम्मीद बनकर उभर सकते हैं। कारण, अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में विभिन्न सरकारों में भिन्न-भिन्न मंत्रीपदों पर रहते हुए उन्होंने कभी ऐसा संकेत नहीं दिया कि वह राष्ट्रीय राजनीति तो दूर, बिहार की राजनीति तक में भी अपनी विशिष्ट उपस्थित दर्ज करा सकते हैं । यही नहीं सोलहवीं लोकसभा चुनाव में जब जदयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 20 मई, 2014 को उन्हें बिहार का ताज सौंपा, तब भी वे लम्बे समय अपनी अलग पहचान बनने में सफल नहीं हो पाए। किन्तु 12 नवम्बर, 2014 को बेतिया में जारी किये गए उनके एक बयान मात्र ने उन्हें न सिर्फ बिहार, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक दुर्लभ नायक के रूप में स्थापित कर दिया।

12 नवम्बर, 2014 को मांझी का मूलनिवासी वाला बयान एक ऐसे समय में आया था जब सामाजिक न्याय के स्थापित नायक/नायिकाओं की गत एक दशक से जारी सवर्ण-परस्त राजनीति से बहुजन समाज निराशा की अतल गहराइयों में डूब चुका था। ऐसे में मांझी के बयान ने जादू सा असर किया किया और बिहार ही नहीं, सम्पूर्ण भारत के समाज परिवर्तनकामी बहुजनों ने उन्हें आंबेडकर और कांशीराम के बाद बहुजन राजनीति की एक नयी उम्मीद के रूप में देखना शुरू किया। बहुजन समाज के प्रबल समर्थन से उत्साहित मांझी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने कथन और कर्म से लगातार बहुजनों के दिलों में जगह बनाते गए। किन्तु उनका लगातार बहुजनों को उद्वेलित करना उनकी ही पार्टी में शामिल सवर्णों और खुद नीतीश कुमार को रास नहीं आया। फलस्वरूप उन्हें 20 फरवरी, 2015 को सीएम पड़ छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। किन्तु मांझी हारकर भी जीत गए। कारण, उन्होंने सत्ता छोड़ने के पूर्व अपने कैबिनेट में जो फैसले लिए थे, वे आजाद भारत में समतामूलक समाज निर्माण के लिहाज से अभूतपूर्व थे। उन्होंने इन फैसलों के द्वारा हिन्दू आरक्षण (वर्ण-व्यवस्था) में शक्ति के स्रोतों से वंचित किये गए दलित/आदिवासी, पिछड़ों और महिलाओं को शक्तिसंपन्न करने का वह एजेंडा प्रस्तुत किया था जो इससे पहले शायद किसी मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया हो।

किन्तु मांझी दूसरे कांशीराम न बन सके

समतामूलक समाज निर्माण में मांझी के फैसलों की प्रभावकारिता को देखते हुए उनके सत्ताच्यूत होने पर देश भर के बहुजनों में समर्थन की और बड़ी सुनामी पैदा हुई। उनके समर्थक यह मानने लगे थे कि अब आगे से बिहार में स्वतंत्र दलित राजनीति का वह नया दौर शुरू होगा, जिसकी शुरुआत यूपी में महान बहुजन नायक कांशीराम ने की थी। बहुजनों के ऐसा सोचने का कारण यह था कि सत्ता से हटने के बाद

मांझी 'हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा '(हम) के बैनर तले ठीक उसी ढंग की राजनीति को आगे बढ़ाते रहे जिसका दृष्टान्त कांशीराम ने स्थापित किया था। उनकी बोली में वही कांशीराम वाली निडर स्पष्टवादिता थी; उन्हें भी अवसरों के इस्तेमाल से परहेज नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह 'हम' के निर्माण-काल से ही आगामी विधानसभा चुनाव में एकला चलो रे की नीति के अवलंबन की घोषणा करते रहे। उनके इस संकल्प को देखते हुए लोग उन्हें बिहार की राजनीति के सबसे निर्णायक नेता के तौर पर देखने लगे थे। किन्तु मांझी एकला चलो के सिद्धांत पर टिके न रह सके, और अंततः राजग की भीड़ में शामिल हो गए। वैसे तो सोशल मीडिया पर आम से लेकर खास, ढेरों लोग ही उनके सीएम पद से हटने के बाद भाजपा में शामिल होने का अनुमान व्यक्त करते रहे। किन्तु मुझ जैसे उनके गुणानुरागी, जिसने मूलनिवासी वाला उनका बयान जारी होने के महीने भर के अंदर उन पर दो किताबें लिख डाला, को बिलकुल ही यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकते हैं। मेरे ऐसा सोचने का खास कारण यह था कि जिस तरह बहुजन समाज ने उन्हें बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर और कांशीराम के बाद सबसे बड़ी शख्सियत के रूप में सम्मान दिया है, वैसे में वे भाजपा में जाकर अपनी ऐतिहासिक छवि को खंडित करने की जोखिम नहीं उठाएंगे, किन्तु उन्होंने उठाया।

मांझी का हिन्दुत्ववादियों के साथ जुड़ना बहुजन राजनीति के लिए एक और ऐतिहासिक आघात था, लिहाजा हमने साक्षात्कार में इस दुखद प्रसंग से जुड़े दो सवाल विद्वान् साक्षात्कारदाताओं के समक्ष रखे। इनमें अनिल कुमार का प्रश्नोत्तर 8 मेरी सोच के काफी करीब है। सचमुच वह एकला चलो की नीति का अवलंबन करते हुए चुनाव में खुद भी नहीं जीत पाते तो भी वह नए कांशीराम बनकर बहुजन राजनीति की उम्मीद बरकरार रखते। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं मांझी को जितना समझ पाया हूँ, मेरे मन के किसी कोने में विश्वास है कि बहुजन समाज ने उन्हें जो प्यार दिया है, उससे वह चैन से कभी सो नहीं पाएंगे। ऐसे में मुमकिन है एक दिन वह घर वापसी कर सकते हैं। बहरहाल किन हालातों में मांझी ने मूलनिवासी वाला बयान जारी किया; कैसे उन्हें लेकर सोशल मीडिया में समर्थन की सुनामी उठी तथा यथास्थितिवादी ताकतों ने कैसे उन्हें सत्ता से हटाने का कुचक्र रचा, यह एक इतिहास है। इस इतिहास को इस वार्षिकी के अध्याय–2 में 200 से ज्यादा पृष्ठों में समेटने का प्रयास हुआ है।

जनगणना–2011

सवर्णवादी राजनीति के खतरनाक रूप से उभार भरे वर्ष में जुलाई 2015 के पहले सप्ताह में आई 'जनगणना-2011' की रिपोर्ट भी बहुजन समाज की परेशानी का एक बड़ा सबब बन गयी। कारण लगभग आठ दशक से जिस जाति आधारित

जनगणना का समाज बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था वह प्रकाशित तो हुई, पर उसमें जाति आधारित आकड़े प्रकाशित नहीं किये गए। किन्तु जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो, इसे लेकर सामाजिक संगठनों से लगाये बहुजनवादी राजनीतिक दल सड़कों पर उतर रहे हैं। इस मामले में लालू प्रसाद यादव औरों से कई कदम आगे हैं। इस मामले में जाति जनगणना पर कई किताबों के लेखक दिलीप मंडल का यह वक्तव्य, जो इस वार्षिकी के पृष्ठ 723 पर छपा है, काफी महत्वपूर्ण है। वह लिखते हैं–'यह तो तय है कि 2011 की जनगणना के बाद जाति की अलग से जो गणना हुई है, उसके नतीजे शायद कभी नहीं आएंगे। राज्य सरकारें इन आकड़ों को मानेंगी भी नहीं। मामला अदालत में जायेगा, इसकी सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस गिनती को जनगणना कानून, 1948 का संरक्षण भी नहीं है। 46 लाख जातियों की जो बात अरुण जेटली ने कही है, उसका हिसाब जोड़ने में ही कई दशक लग जायेंगे। इसलिए इस जाति जनगणना को भूल जाना ही उचित है। जनगणना कराने में सिर्फ एक महीने का समय लगता है। हर दस साल पर फरवरी महीने में देश भर में जनगणना हो जाती है। सरकारी मशीनरी को यह काम करने का इतना बेहतरीन अभ्यास है कि कभी कोई चुक नहीं होती। जनगणना से पहले हाउस लिस्टिंग होती है। 2011 के अकड़े सरकार के पास मौजूद हैं। सरकार अगर चाहे तो तीन महीने की तैयारी के बाद चौथे महीने जनगणना कराकर नियत समय में जाति जनगणना के आकड़े जारी कर सकती है। सवाल नीयत के साफ होने या नहीं होने का है। केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए कि सरकार आपकी नीयत कैसी है?'

बहरहाल जाति जनगणना से सरकारों और अदालतों को इसलिए एलर्जी है क्योंकि उन्हें पता है कि इससे यह बात ढकी-छुपी नहीं रहेगी कि शक्ति के स्रोतों पर अल्पजन सवर्णों का 80-85 प्रतिशत कब्जा है। यह स्थिति साफ होने पर बहुजनों में विद्रोह की अग्नि प्रज्ज्वलित होगी, लिहाजा वे ऐसी जनगणना को रोकने में सर्वशक्ति लगाते रहते हैं। किन्तु जो लोग यह महसूस करते हैं की शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन के जरिये ही समतामूलक समाज निर्माण किया तथा भारतीय लोकतंत्र को सबकी भागीदारी वाला लोकतंत्र बनाया जा सकता है, उन्हें सबसे पहले जाति-जनगणना के लिए सर्वशक्ति लगानी होगी।

बढ़ता ही जा रहा है : नस्ल और जाति-भेद

इस बार की डाइवर्सिटी इयर बुक के जरिये हम यह अप्रिय घोषणा करने के लिए बाध्य हैं कि दुनिया में जन्मगत आधार पर शोषण और उत्पीड़न, जिसका चरम प्रतिबिम्बन भारत की जाति और अमेरिका के नस्ल- भेद व्यवस्था में हुआ, आज फिर उभार पर है। अमेरिका में जहां इसके उभार का लक्षण फर्ग्यूसन कांड और

87वें ऑस्कर में प्रकट हुआ है, वहीं भारत में भगाणा के बाद इसकी वीभत्सता का दर्शन राजस्थान के जालौर, उप्र के शाहजहांपुर और बिहार के लखीसराय और खगड़िया काण्ड में देखा जा सकता है। अमेरिका में जहां इसके पीछे ओबामा के राष्ट्रपति बनने से इर्ष्याग्रस्त हुए व्हाइट सुपरमिस्टों का उभार है, वहीं भारत में इसके पृष्ठ में मानवेतरों(दलितों) के जीवन में आये थोड़े से बदलाव से जले-भुने हिन्दू-सुपरमिस्टों की क्रियाशीलता है। बहरहाल अमेरिका में व्हाईट सुपरमिस्टों के मनोबल को ध्वस्त करने के लिए नागरिक अधिकारों की प्रथम महिला रोजा मैकाले पार्क्स के लोगों ने फर्ग्यूसन प्रोटेस्ट को जरिया बना लिया है, किन्तु भारत में स्थिति उल्टी है। यहां की सिविल सोसाइटी, न्यायपालिका और मीडिया तो हिन्दू सुपरमिस्टों के फेवर में थी ही, पर अब दलित नेता भी अपने समाज के लोगों पर हो रहे है जुल्मो-सितम पर खामोशी अख्तियार करना सीख गए हैं। अब इनकी सवर्ण-परस्ती से आहत दलित समुदाय ने औरों को अपना त्राता मानना शुरू कर दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ खगड़िया के परबत्ता कांड के शिकार लोगों के आंसूं पोछने में जुटे मधेपुरा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मिला है। इस काण्ड विशेष ने उन्हें दलितों का हीरो बना दिया है।

आज जरूरत है एक नए नामदेव ढसाल की

बहरहाल पिछले वर्ष हमने जिस भगाणा कांड के पीड़ितों के लिए इयर बुक में 80 से अधिक पृष्ठ आरक्षित किया, उन्होंने हर तरह से निराश होकर 8 अगस्त, 2015 को इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसके लिए उन्हें किसने मजबूर किया, उस पर 'भगाणा पीड़ितों के धर्मान्तरण के लिए जिम्मेवार कौन' नामक अपने आलेख में मैंने विस्तार से रोशनी डाली है। किन्तु हिन्दू-सुपरमिस्टों का इलाज क्या हो, उसके लिए मैंने फर्ग्यूसन प्रोटेस्टरों से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया है। वैसे तो सख्त के भक्त हिन्दू सुपरमिस्टों का इलाज शक्ति के तमाम स्रोतों में दलित समुदाय की हिस्सेदारी है, परन्तु इसके साथ तात्कालिक इलाज फर्ग्यूसन प्रोटेस्ट से प्रेरणा लेने में है। कभी 22 वर्षीय नामदेव ढसाल और उनके साथियों ने अमेरिका के 'ब्लैक पैन्थर' से प्रेरणा लेकर 'दलित पैंथर' बनाया और हिन्दू सुपरमिस्टों को चूहों की भांति बिलों में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे में आज जरुरत एक नए ढसाल की है।

आरक्षण पर जारी अनंत संघर्ष को टालने के लिए : डाइवर्सिटी

इन पंक्तियों के लिखे जाने के दौरान जाट और गुर्जर जैसी सक्षम जातियों से भी ज्यादा सक्षम गुजरात के पाटीदारों ने आरक्षण पर एक नए संघर्ष का बड़े पैमाने पर आगाज कर दिया है। उनकी देखा-देखी वहां के ब्राह्मणों ने भी गरीब ब्राह्मणों के आरक्षण की मांग बुलंद कर दी है। हालांकि इनका लक्ष्य अपना आरक्षण लेना

कम, पहले से वंचित जातियों के लिए जारी आरक्षण का खात्मा ज्यादा है। जाट और गुर्जर आरक्षण के प्रसंग में इयर बुक के जरिये कई बार समाधान डाइवर्सिटी में ढूँढ़ने का सुझाव दिया गया है। अब जाटों और गुर्जरों से ज्यादा सक्षम पाटीदारों की आरक्षण की मांग को देखते हुए यही कहना चाहूंगा आरक्षण की अनंत लड़ाई से राष्ट्र को निजात दिलाने के लिए जरुरी है शक्ति के सभी प्रमुख स्रोतों (आर्थिक-राजनीतिक-धार्मिक) में सामाजिक और लैंगिक विविधता के प्रतिबिम्बन का कानून जल्द से जल्द लागू हो। क्योंकि आज जिस तरह नौकरियों में आरक्षण के लिए नए-नए समूह मैदान में उतर रहे हैं, वैसे ही कल दलित-आदिवासियों के साथ सप्लाई, डीलरशिप, ठेकों, पार्किंग-परिवहन, फिल्म-टीवी, पौरोहित्य इत्यादि में आरक्षण के लिए शेष बचे समुदायों के स्त्री-पुरुष भी मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में आरक्षण पर संघर्ष के चिर-स्थाई हल के लिए तमाम क्षेत्रों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करने से बेहतर और कोई उपाय नहीं रह गया है।

नेपाल के संविधान में डाइवर्सिटी

आज की तारीख में नेपाल में लोकतंत्र को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए एक संविधान के गृहित होने की प्रक्रिया शेष चरण में है। संविधान के ड्राफ्ट की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उसकी उद्देश्यिका में वहां की तरह-तरह की विविधताओं (डाइवर्सिटीज) को सम्मान देते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आनुपातिक भागीदारी की बात खुलकर कही गयी है। पर इसका उल्लेख किसी धारा में नहीं है। किन्तु आनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए वहां के अम्बेडकरवादी और दलित माओवादी सर्वशक्ति लगा रहे हैं। इस सिलसिले में नेपाल की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य विश्वेन्द्र पासवान ने भारत का नैतिक समर्थन हासिल करने के लिए 9 से 27 जुलाई तक लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के लेखक, एक्टिविस्टों और छात्रों के मध्य कई बैठकें कीं। यहां के लोगों ने उन्हें नेपाल के आंबेडकर के रूप में अपने हृदय सिंहासन पर बिठाया। पासवान साहब नेपाल के संविधान में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भारत में सवर्णों के समक्ष घुटने टेक चुके बहुजनवादी नेताओं के मुंह में इतने दांत नहीं है कि वे बहुजनों के लिए हर क्षेत्र संख्यानुपात में भागीदारी की मांग उठा सकें। किन्तु यदि नेपाल में अम्बेडकरवादी विश्वेन्द्र पासवान और दलित माओवादियों की आनुपातिक भागीदारी की लड़ाई सफल होती है तो, उसका लाभ बहुजन भारत को भी मिल सकता है, यह सोच कर ही हमने इस वार्षिकी का अंतिम अध्याय नेपाल में संविधान निर्माण और भागीदारी के प्रश्न को समर्पित किया है।

लगता है नहीं बनेगा मंडल, कमंडल की काट

इयर बुक का यह अंक जब पाठकों के बीच पहुंचेगा, उस समय तक बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार तुंग पर पहुँच चुका होगा, जिस पर पूरे देश, खासकर बहुजन भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुजन भारत के लोग यह तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि नीतीश-लालू मिलकर भाजपा की वह गति कर देंगे जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनजीओ गैंग ने कर डाला। महागठबंधन से बस इतनी ही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह उसने पिछले साल बिहार विधानसभा के उपचुनाव में राजग को शिकस्त दी थी, अंततः उतना करके दिखा दे। किन्तु लगता नहीं है बहुजनों की उम्मीद पूरी होगी। इसका कारण यह है कि जिस लालू-नीतीश ने मिलकर बिहार पर 25 साल शासन किया वे बिहारवासियों के सामने ऐसा कोई सपना नहीं परोस रहे हैं, जिसे पूरा करने के लिए लोग उन्हें वोट दें।

गत वर्ष बिहार विधानसभा उपचुनाव के कुछ सप्ताह पहले लालू प्रसाद यादव ने भाजपा को रोकने के लिए कहा था, 'मंडल ही बनेगा कमंडल की काट'। मंडलवादी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ठेकों सहित विकास की तमाम योजनाओं में दलित, आदिवासी, पिछड़ों और अकलियतों के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण हेतु सड़कों पर उतरने का एलान कर दिया था। इसका लाभ गठबंधन को भाजपा गठबंधन की हार के रूप मिला। उपचुनाव के बाद उम्मीद थी कि बिहार विधानसभा चुनाव-2015 को दृष्टिगत रखते हुए मंडलवादी एजेंडे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए नीतीश-लालू अविराम अभियान चलाएंगे। क्योंकि कमंडलवादियों की काट के लिए मंडल ही एक अचूक हथियार था। किन्तु इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उनमें इसके इस्तेमाल कोई खास रूचि नहीं दिख रही है। लिहाजा बहुजन भारत को भाजपा गठबंधन की हार देखने के लिए अब किसी चमत्कार पर निर्भर रहना होगा।

अंत में। आभारी हूँ उन पत्र-पत्रिकाओं का जिनमें छपे लेखों से इयर बुक : 2015-16 समृद्ध हुई है। आभारी हूँ लेखक बंधुओं का जिनके लेखों और साक्षात्कार के बिना यह अंक बेजान लगता। हर बार की तरह एक बार फिर डाइवर्सिटी मूवमेंट को तन-मन-धन से आगे बढानेवाले मा. बुद्ध शरण 'हंस', डॉ. संजय पासवान, मा. छेदी पासवान, डॉ. विजय कुमार त्रिशरण, मा. दिलीप मंडल, मा. सुरेश केदारे, मा. बृजपाल भारती, मा. अनिल कुमार आर्य, मा. ललन कुमार, मा. अभिजित कुमार, डॉ. राजीव, डॉ. राज बहादुर मौर्य, मा. शीलबोधि, डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी, मा. पंकज पासवान, मा. निर्मल पासवान को अशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से नियमित अंतराल पर डाइवर्सिटी साहित्य लोगों के बीच पहुँच रहा है।

!! जय भीम-जय भारत !!

दसवाँ डाइवर्सिटी डे
(13 सितम्बर, 2015)

–एच.एल. दुसाध
(संपादक, डाइवर्सिटी इयर बुक)

अनुक्रम

सम्पादकीय 5

अध्याय-1

मिशन डाइवर्सिटी

डाइवर्सिटी आर्थिक अवसरों के असमान व अन्यायपूर्ण वितरण के खिलाफ एक मुहिम है—*शीलबोधि* 29

भविष्य का मुद्दा डाइवर्सिटी ही है—*एच.एल. दुसाध* 35

बहुजन डाइवर्सिटी मिशन का नवां 'स्थापना दिवस' समारोह 38

अध्याय-2

बहुजन राजनीति की नई उम्मीद जीतनराम मांझी

अध्याय-2 ए : बिहार के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री : जीतनराम मांझी

सामाजिक न्याय का चमत्कार—*अरुण कुमार त्रिपाठी* 43

मांझी पर पार लगाने की जिम्मेदारी—*अशोक दास* 46

मांझी का मोहभंग—*अशोक त्रिपाठी* 52

सवर्ण घृणा के शिकार मांझी : इतिहास में इसके उदाहरण पहले भी मिलते हैं—*संजीव चंदन* 55

अध्याय-2 बी : सोशल मीडिया में उठी मांझी समर्थन की सुनामी

अमर आजाद, देशदीपक बौद्ध, दिलीप मंडल, हरिशंकर शाही, वेदप्रकाश, एच.एल. दुसाध 58

अध्याय-2 सी : मांझी के नये अवतार पर बुद्धिजीवियों की राय

मांझी जैसे लोग ही अब बन सकते हैं नए बहुजन नायक—*एच.एल. दुसाध* 111

जदयू का भटकाव—*निशिकांत ठाकुर* 114

जीतनराम मांझी बने बहुजन नायक—*डॉ. कौशल पंवार* 117

मूलनिवासी बनाम विदेशी पर गहन चिंतन की आवश्यकता है—*हरिशंकर शाही* 120

मांझी मुख्यमंत्री : बयान पर बवाल—जितेंद्र यादव 123

क्या मांझी की जुबान सचमुच फिसल रही है?—*प्रणय प्रियंवद* 127

समाज के प्रति कर्ज चुकाना चाहते हैं मांझी—*देशदीपक बौद्ध* 129

जीतनराम मांझी को सच कहने की हिम्मत है—*बुद्ध शरण हंस* 131

जीतन राम माँझी के बयान में जनक्रान्ति की धमक—*डॉ. विजय कुमार त्रिशरण* 138

अध्याय-2 डी : तैयार हुई मांझी के रुखसती की पटकथा
बिहार की राजनीति पर दीर्घतर होती मांझी की छाया—*एच.एल. दुसाध* 142
जदयू विधायकों के नाम शिवानंद तिवारी की खुली चिट्ठी 144
नीतीश-मांझी में जोर आजमाइश 146
बिहार पर निगाह 147
जनता कुनबे में दरार —*सुभाष कश्यप, वरिष्ठ संविधानविद्* 149
संवैधानिक संकट की स्थिति है —*संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक* 150
पासवान ने की विधानसभा भंग करने की मांग 151
'मुझे रबर स्टांप बनाना चाहा' 152
भाजपा का खिलौना बन रहे मांझी : त्यागी 152
मांझी का फैसला 20 को 153
मुझे खिलौना समझना नीतीश की महागलती 155
पप्पू यादव व रंजीता रंजन मुख्यमन्त्री मांझी पर रीझे 156
बिहार फिर भंवर में —*ए.के. वर्मा* 158
वसंत का वज्रनाद और बिहार की राजनीति —*प्रेम कुमार मणि* 160
सामाजिक न्याय की परंपरा से जुड़िए नीतीश कुमार 163
मांझी को हाईकोर्ट का झटका 166
बिहार में सभी विकल्प खुले : भाजपा 168
मांझी का दावा-हासिल करेंगे बहुमत 169
मांझी भाजपा विरोधियों का इतिहास भी देंखे —*एच.एल.दुसाध* 171
महादलितों के सम्मान की खातिर समर्थन का फैसला 174
चार बागी नहीं डाल पायेंगे वोट 175
नीतीश आवास 177
मांझी कैबिनेट ने लगायी तोहफों की झड़ी 179
नीतीश कुमार समय को पहचानें : शकुनी 181
जीतन राम मांझी खेमे को हाईकोर्ट ने दिए तीन झटके 182
जदयू और कांग्रेस ने ह्विप जारी किया 184
पप्पू यादव ने दिया ऊंचे पद का प्रलोभन : शर्फुद्दीन 185
अभिभाषण का बहिष्कार करेगा महागठबंधन 186
असली फैसला तो जनता ही करेगी —*पुण्य प्रसून वाजपेयी* 187
अध्याय-2 ई : मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मजबूर हुए मांझी
मांझी का इस्तीफा, नीतीश को न्योता 190
मरहम से होगा लाभ तो जख्म कुरेदने से भी—*एसए शाद, पटना* 191

शाम तक थक सा गया दिखा एक अणे मार्ग —*अनिल सिंह झा, पटना* 192
नई सरकार के रास्ते पर बिछे एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों
शूल संभलकर चलना होगा —*राजीव रंजन, पटना* 193
संसदीय लोकतन्त्र की अभूतपूर्व घटना 196
देर रात ही हो गया था निर्णय 199
और भाजपा का गेम प्लान फेल हो गया 201
चुनावी साल है, मांझी के मायने अभी कई होंगे —*अरविंद शर्मा, पटना* 204
जनवरी से मार्च के बीच बिहार के 22 मुख्यमन्त्री बदले —भुवनेश्वर वात्स्यायन 205
नहीं थी न्याय की उम्मीद 206
मुझे हटाने को सभी हथकंडे अपनाए : मांझी 207
विधायकों को संकट में नहीं डालना चाहता था 208
अध्याय-2 एफ : और मांझी हार के भी जीत गए
20 को शुरू हुई पारी 20 को ही खत्म 210
बिहार में लोकतन्त्र शर्मसार 211
कौरवों ने घेरकर कर दी 'अभिमन्यु' की हत्या 212
फेसबुक की प्रतिक्रिया 214
राजनीति के मध्य में मांझी —*अमिताभ श्रीवास्तव* 219
चुनाव में 70 प्रतिशत टिकट गरीबों को देगा 'हम' 222
अकेले दम पर चुनाव लड़ेगा 'हम' 223
मांझी की रैली : सोदेबाज़ी के हुनर की परीक्षा—*विनोद बंधु, वरिष्ठ पत्रकार* 225
अध्याय-2 जी : मांझी में अभी भी बची है सम्भावना : दुसाध
मांझी की बोली में गोली सा असर 228
अब लालू की दलित राजनीति का क्या होगा? 230
अब सचमुच बहुजनों की उम्मीद बन गए हैं मांझी 231
और मांझी हारकर भी जीत गए 232
गांधी मैदान में हुई मांझी की उपलब्धियों की परीक्षा 233
लॉन्ग लिव डाइवर्सिटी-लॉन्ग लिव मांझी 234
मांझी में अभी भी बची है बहुजन राजनीति की संभावना 236
मांझी की बोली में कांशीराम की झलक 237
मांझी के आत्मविश्वास का राज : बिहार स्वतंत्र दलित राजनीति का उत्थान 238
मांझी ने जगाई डाइवर्सिटी एजेंडा अपनाने की उम्मीद 240
मांझी ने पेश किया आर्थिक बदलाव का आजाद भारत के
इतिहास का सबसे बड़ा क्रन्तिकारी प्रोग्राम 242

मांझी सरकार की विशेष उपलब्धि : महिला सशक्तिकरण 243
लालू को दलित विरोधी बनाने के लिए जिम्मेवार कौन? 244
स्वाभिमानी मांझी ने सत्ता छोड़ने से किया इनकार 245
'हम' सचमुच साबित होगा 'आप' का बाप 247
हम का लक्ष्य : आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी का खात्मा 248
बिहार में ठेकों में आरक्षण के पीछे मंडलवादी राजनीति तो नहीं! 251

अध्याय-3

फिर केजरीवाल

अध्याय-3 ए : पांच साल केजरीवाल

बोए पेड़ बबूल...—*गुलाब कोठारी* 257
पार्टियों के लिए परिणाम के क्या हैं मायने 258
दूर तक जाएगी गूंज 259
ये पहुंचे सदन 261
वाह अभिमन्यु... 263
भविष्यवाणी गलत होने पर भी खुश—*योगेन्द्र यादव* 264
केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ 266
क्या बोले केजरीवाल 267
जनता ने फिर दिखाई ताकत 268
सब पर नजर रखेंगे केजरीवाल 270
ये हैं आप सरकार की प्राथमिकताएं 271
वादों की समय सीमा देने से बच रहे सीएम—*मुकेश केजरीवाल* 273
मोदी और भाजपा के लिए कुछ नसीहतें—*चेतन भगत* 275
वरदान है यह हार भाजपा के लिए—*वेदप्रताप वैदिक* 277
भाजपा की गलतियां —*ए. सूर्यप्रकाश* 279
जबरदस्त जीत का संदेश—संजय गुप्त 281
वैकल्पिक राजनीति का अभ्युदय—*आशु नारायण राय* 284
दिखेगा समीकरणों में बदलाव—*नीरजा चौधरी* 286
नतीजों का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी—*प्रो. जगदीप छोकर* 287
वादाखिलाफी पर गुस्से का इजहार—*प्रो. मणींद्रनाथ ठाकुर* 288
खुला है आसमां 289
विकल्प की चाह हर जगह—*उर्मिलेश* 290
बाहर तो निकलेंगे ही...—*नीरजा चौधरी* 291
शहरी गरीब बन सकते हैं वोट बैंक—*संजय कुमार* 293

अल्पसंख्यक आएंगे करीब—*कमर वहीद नकवी* 295
चुनावी संग्राम का पुनर्पाठ—*रामबहादुर राय* 296
सामाजिक आधार में आए बदलाव के नतीजे —*यशवंत देशमुख* 299
लोकविमुख राजनीति के खिलाफ बगावत—*अनिल जैन* 302
दिल्ली-दोहराव की मुश्किलें—*अरविंद मोहन* 305
दखल और बढ़ेगा सोशल मीडिया का—*बालेन्दु शर्मा दाधीच* 308
अस्मिताओं के वोट से परहेज नहीं—*प्रो. विवेक कुमार* 310
भाजपा न करेगी आत्ममंथन न ही सीखेगी कोई सबक—*अवधेश कुमार* 312
जीवन लोकतांत्रिक उपायों में —*सुधा पई* 314
दिल्ली ने चेताया नरेन्द्र मोदी को—*जवाहर लाल कौल* 317
आप के बाद बल्ले-बल्ले सेना —*सतीश पेडणेकर* 319
सरकार बनाने पर तुरंत फैसले का दबाव बढ़ा—*पुष्प सर्राफ* 322
देश में अब विपक्ष की भूमिका—*राजेन्द्र शर्मा* 324
दिल्ली का दंगल और सामाजिक विविधता के प्रश्न—*डॉ. रतनलाल* 326
तीसरी धारा, बीएसपी और वामपंथ का विलोपवाद—*दिलीप मंडल* 332
केजरीवाल को अग्रिम बधाई—*एच.एल. दुसाध* 336
बिन मांगे केजरी को समर्थन देने की होड़—*एच.एल. दुसाध* 338
दिल्ली विधानसभा चुनाव : लोकतंत्र की ध्वंस की दिशा में
एक और कदम —*एच. एल. दुसाध* 339
केजरी को समर्थन : बहुजन राजनीति के पतन की पराकाष्ठा—*एच.एल. दुसाध* 342
भारतीय राजनीति में आप की स्थायी उपस्थिति —*एच.एल. दुसाध* 345

अध्याय-3 बी : आप में बिखराव

फिर टूटा वैकल्पिक राजनीति का स्वप्न—*विभांशु दिव्याल* 346
विसर्जन का अरविंद मार्ग —*राजकिशोर* 348
एक सुंदर सपने का अंत —*राजीव सचान* 350
गलत सपने का सच है 'आप' भुलाना बेहतर —*प्रो. आनन्द कुमार* 353
विरोध करने वाले कुंठित लोग मुंह के बल गिरेंगे —*संजय सिंह* 358
आप तो ऐसे न होने वाले थे! —*राजेन्द्र शर्मा* 360
'वह' इकबाल और न खौफ —*रत्नेश मिश्र* 363
वैकल्पिक राजनीति का गर्भपात है यह —*अनिल जैन* 365
बंद मुट्ठी लाख की, खुलने पर खाक की —*अरविंद मोहन* 367
जब मांझी नाव डुबाए तो कौन बचाए! —*प्रदीप सिंह* 370
व्यक्तिवादी राजनीति का पाखंड —*अरविंद कुमार सिंह* 372

Continue Your Reading Journey

This preview has ended. Access the complete library and support our mission.

Join Our Inclusive Reading Community

✓ We champion diverse voices and perspectives

✓ Your support helps amplify underrepresented authors

✓ We provide free access to educational institutions

✓ Building bridges through shared stories

✓ Creating space for all narratives to be heard

Support Our Mission

Your donation enables us to:

• Curate diverse book collections

• Support authors from marginalized communities

• Provide free resources to educators

• Maintain our accessible digital library

Visit: www.diversitymission.in

Sign the diversity pledge • Make a donation • Download full library